RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®

इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 20 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 भोपाल , मध्यप्रदेश से प्रकाशित वर्ष- 13 अंक-71 पृष्ठ- 8 मूल्य- रु. 5 /-

अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट: 25 दिसंबर को ग्वालियर में विकास का महाकुंभ

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में निवेश और उद्योगों का बड़ा आयोजन; टियर-2 शहरों को हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार 'अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट' का आयोजन 25 दिसंबर 2025 को ग्वालियर में करने जा रही है। यह समिट राज्य के टियर-2 और टियर-3 शहरों को औद्योगिक और निवेश हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में यह आयोजन राज्य की आर्थिक प्रगति को नई गति देगा।

समिट में उद्योगपति, निवेशक, स्टार्टअप्स और नीति निर्माताओं की भागीदारी होगी। मुख्य फोकस आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, टूरिज्म, एग्री-प्रोसेसिंग और ग्रीन एनर्जी सेक्टर पर रहेगा। ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की संभावनाओं को उजागर करते हुए बड़े निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पिछले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट की सफलता के बाद यह समिट राज्य की GDP को दोगुना करने के लक्ष्य को मजबूत करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा, अभ्युदय मध्य प्रदेश का अर्थ है हर क्षेत्र का समग्र विकास। ग्वालियर जैसे शहरों को निवेश का केंद्र बनाकर हम युवाओं को रोजगार और उद्यमिता के अवसर देंगे। समिट में सिंगल विंडो क्लीयरेंस, लैंड बैंक और सब्सिडी नीतियों पर चर्चा होगी। टियर-2 शहरों में इंफ्रा विकास जैसे एयरपोर्ट, हाईवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर विशेष सत्र होंगे।

यह आयोजन विकसित भारत 2047' के विजन से जुड़ा है, जहां मध्य प्रदेश 2030 तक 350 अरब डॉलर अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखे हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समिट 50,000 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित कर सकती है। ग्वालियर के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए यह आयोजन पर्यटन को भी बढ़ावा देगा। समिट राज्य की प्रगति का नया अध्याय लिखेगी।

संसद ने बीमा क्षेत्र में 100% FDI बिल पास किया: विदेशी कंपनियां अब पूरी मालिक बन सकेंगी

प्रीमियम सस्ता होने की उम्मीद, पूंजी प्रवाह बढ़ेगा; विपक्ष की चिंताओं के बावजूद लोकसभा-राज्यसभा से मंजूरी

नई दिल्ली: संसद ने बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) की सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने वाला संशोधन विधेयक पास कर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश 'बीमा कानून (संशोधन) विधेयक 2025' लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मंजूरी मिल गई। अब विदेशी कंपनियां भारतीय बीमा कंपनियों में पूर्ण स्वामित्व रख सकेंगी, जो पहले 74% तक सीमित था।

सरकार का दावा है कि इससे बीमा क्षेत्र में भारी पूंजी आएगी, नए उत्पाद आएंगे और प्रीमियम सस्ता होगा। बीमा घनत्व बढ़ेगा, जो वर्तमान में 4.2% है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच बढ़ेगी। IRDAI केसख्त नियामक ढांचे से राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की गई है। भारतीय प्रबंधन और नियंत्रण की शर्त बरकरार रहेगी।

विपक्ष ने विधेयक का विरोध किया, चिंता जताई कि विदेशी कंपनियां डेटा और बाजार पर नियंत्रण कर सकती हैं। कांग्रेस और अन्य दलों ने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि FDI से रोजगार सृजित होगा और बीमा क्षेत्र 2030 तक 500 अरब डॉलर का हो जाएगा।

यह बदलाव 'बीमा सबके लिए 2047' विजन का हिस्सा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे 50-100 अरब डॉलर FDI आएगा, जो LIC, SBI लाइफ जैसी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूत बनाएगा। प्रीमियम में 10-15% कमी की उम्मीद है। विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा। यह कदम भारत को वैश्विक बीमा हब बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

CAG ने कोल इंडिया की 3,000 MW सोलर परियोजनाओं में देरी पर जताई चिंता

दिसंबर 2024 तक केवल 122 MW क्षमता स्थापित, लक्ष्य का मात्र 4.08%; नेट जीरो लक्ष्य के लिए फास्ट-ट्रैक जरूरी

नई दिल्ली: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) की 3,000 MW सोलर पावर परियोजनाओं में भारी देरी पर कड़ी आपत्ति जताई है। CAG की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2024 तक कंपनी और उसकी सहायक इकाइयों ने केवल 122.492 MW सोलर क्षमता स्थापित की है, जो लक्ष्य का मात्र 4.08% है। सरकार ने 2017 में CIL को 2024 तक 3,000 MW सोलर पावर विकसित करने का जिम्मा सौंपा था, ताकि कंपनी नेट जीरो एनर्जी कंपनी बन सके।

रिपोर्ट में कहा गया है कि CIL ने NTPC और NLC इंडिया के साथ 1,000 MW प्रत्येक की जॉइंट वेंचर बनाईं और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के साथ MoU किया। इसके अलावा, CIL नविकरणीय ऊर्जा लिमिटेड नामक SPV बनाया गया, लेकिन प्रगति धीमी रही। सीएजी ने CIL को परियोजनाओं को फास्ट-ट्रैक करने की सलाह दी है, ताकि नेट जीरो लक्ष्य हासिल हो सके। कोल इंडिया देश का 80% कोयला उत्पादन करती है, लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा में पिछड़ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि देरी से भारत के 500 GW नॉन-फॉसिल लक्ष्य (2030) पर असर पड़ सकता है। CIL ने हाल ही में कुछ सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर जारी किए हैं, लेकिन कार्यान्वयन में बाधाएं बनी हुई हैं।

यह रिपोर्ट कोयला क्षेत्र के हरित परिवर्तन की चुनौतियों को उजागर करती है। सरकार ने नेट जीरो के लिए नई समय सीमा तय की है, लेकिन CIL को तेजी दिखानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि JV और SPV को मजबूत करने से प्रगति हो सकती है। कोल इंडिया के शेयर इस खबर से मामूली गिरावट पर बंद हुए। यह मुद्दा ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण संतुलन का सवाल उठाता है।

लार्सन एंड टुब्रो ने मल्टी-करोड़ प्रोजेक्ट्स हासिल किए: सऊदी अरब और भारत में बड़ा ऑर्डर

पावर ट्रांसमिशन, सोलर और इंफ्रा सेक्टर में मजबूती; FY26 ऑर्डर बुक में 5,000 करोड़ का इजाफा, वैश्विक विस्तार को गति

मुंबई:इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन दिग्गज लार्सन एंड टुब्रो (L&T) ने सऊदी अरब और भारत से मल्टी-करोड़ रुपये के बड़े प्रोजेक्ट्स हासिल किए हैं। कंपनी ने मंगलवार को बीएसई फाइलिंग में घोषणा की कि उसके पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन (PT&D) और सोलर एनर्जी बिजनेस ने कुल 5,000 करोड़ से अधिक के ऑर्डर बुक किए हैं। इनमें सऊदी अरब में हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स और सबस्टेशन प्रोजेक्ट्स प्रमुख हैं, जो विजन 2030 के तहत रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन से जुड़े हैं।

भारत में L&T ने महाराष्ट्र और गुजरात में सोलर प्लांट्स और ग्रिड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हासिल किए। कंपनी के सीईओ एस.एन. सुब्रह्मण्यन ने कहा, ये ऑर्डर हमारी वैश्विक क्षमता और सस्टेनेबल इंफ्रा पर फोकस को दर्शाते हैं। सऊदी में हमारा फुटप्रिंट बढ़ रहा है, जबकि भारत में रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन को सपोर्ट कर रहे हैं। PT&D बिजनेस ने सऊदी से 2,500 करोड़ और भारत से 1,500 करोड़ के ऑर्डर जीते। सोलर सेगमेंट में 1,000 करोड़ का योगदान है।

L&T की कुल ऑर्डर बुक अब 5 लाख करोड़ के पार है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय ऑर्डर 40% हैं। कंपनी FY26 में 20% राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखे हुए है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये ऑर्डर L&T को मध्य पूर्व और भारत के इंफ्रा बूम से लाभ दिलाएंगे। शेयर बाजार में L&T के शेयर 2.5% चढ़कर 3,950 रुपये पर बंद हुए।

Government Unveils Credit Guarantee Scheme to Alleviate MFI Stress

New Fund to Cover 80% of Defaults; Targets Rs 50,000 Cr Fresh Lending to Micro-Borrowers Amid Rising NPAs

New Delhi: In a major relief measure for the microfinance sector grappling with rising non-performing assets (NPAs), the government is finalizing a credit guarantee scheme to encourage banks to resume lending to microfinance institutions (MFIs). The initiative, discussed in a high-level meeting chaired by Finance Minister Nirmala Sitharaman on Tuesday, aims to unlock Rs 50,000 crore in fresh credit flow to low-income borrowers, particularly women in rural and semi-urban areas.

Under the proposed scheme, a dedicated fund likely managed by the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) will provide up to 80% coverage on defaults for loans extended to MFIs. This addresses banks' caution following a spike in MFI NPAs to 4-5% in H1 FY26, driven by over-indebtedness and regional repayment issues in states like Tamil Nadu and Assam.

The scheme will restore confidence in the sector, ensuring continued financial inclusion without burdening taxpayers, an official said. It complements existing PLI incentives and RBI's prompt corrective action framework for NBFC-MFIs. The fund corpus is pegged at Rs 5,000-10,000 crore initially, with contributions from the government and participating lenders.

Industry bodies like MFIN welcomed the move, projecting a 15-20% lending revival in FY26. With microfinance outstanding at Rs 4 lakh crore serving 12 crore clients, the scheme could avert a credit crunch threatening 1.5 lakh jobs in the sector.

Implementation details, including eligibility and premium rates, are expected in the Union Budget 2026. As India targets 100% financial inclusion by 2027, this guarantee mechanism promises to sustain momentum in empowering marginalised borrowers while safeguarding lender balance sheets.

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

Mid-Cap & Small-Cap Funds After the Rally: Time to Be Cautious or Stay Invested?

After a strong run in Indian equity markets, mid-cap and small-cap funds have been in the spotlight. These funds, which invest in medium and smaller companies, delivered strong returns in recent years, significantly outperforming many large-cap funds. However, with valuations running high and market conditions becoming uncertain, many investors are now asking: Is it time to be cautious or stay invested for the long term?

To understand this, let's look at how these segments have performed and what experts are saying. Data from the Nifty Midcap 150 Total Return Index shows that over long periods such as 10 years, mid-cap stocks generated average returns of around 16.2% per year, higher than broader market indices like the Nifty 500 over the same horizon. The Nifty Smallcap 250 Total Return Index also delivered strong returns of about 13.5% per year over a decade indicating the potential of smaller companies to create wealth if held long enough.

Individual mutual funds have mirrored this trend. According to market data, many mid-cap and small-cap mutual funds have delivered impressive annualised returns ranging from 25% to nearly 40% over the past five years. For example, in mid-cap funds like Quant Mid Cap Fund and Motilal Oswal Midcap Fund, a five-year investment of ₹75,000 could have grown to around ₹2,50,000 to ₹2,79,000, while top small-cap funds like Quant Small Cap Fund delivered even higher growth.

This strong performance has driven retail interest. During the first quarter of 2025, mid-cap and small-cap schemes together attracted more than ₹20,000 crore from retail investors, even as valuations climbed. However, strong returns often lead to higher valuations. When prices rise faster than company profits, future returns may slow down or become volatile. This is especially true for smaller companies, which tend to react more sharply to changes in market sentiment.

Recently, markets have seen mixed performance. While mid-cap and small-cap indices have posted modest gains, broader market indices like the Nifty 50 have remained relatively flat amid global uncertainties and foreign investor outflows. This highlights the importance of being cautious, especially in the short term.

Yet, long-term prospects remain appealing. Many analysts believe mid-cap and small-cap stocks are turning attractive again as corporate earnings begin to revive after a period of consolidation. Industry experts suggest that these segments could benefit from renewed growth and improved earnings momentum in the coming years.

For long-term investors, a balanced approach may work best. Instead of exiting completely, continuing SIPs (Systematic Investment Plans) can help manage market volatility while preserving participation in future growth. SIPs spread investments over time, reducing the risk of poor timing. Additionally, if your portfolio's exposure to mid- and small-cap funds has grown disproportionately after the rally, rebalancing part of your holdings into more stable large-cap or diversified funds can reduce risk.

In simple words, this is not a time for panic, but it is a time for prudence and discipline. Mid-cap and small-cap funds still have the potential to create long-term wealth, especially if you remain patient and invest with a clear plan. Markets move in cycles; being cautious today does not mean missing tomorrow's opportunities. The key is to stay invested with the right strategy.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

महिंद्रा अब भारत में लगभग आधी डीजल कारें अकेले बेच रहा है

SUV सेगमेंट में डीजल की हिस्सेदारी 50% पार, पेट्रोल-इलेक्ट्रिक से आगे; ग्राहक पसंद और माइलेज से प्रेरित ट्रेंड

मुंबई : महिंद्रा एंड महिंद्रा (M&M) ने भारतीय ऑटो बाजार में डीजल की मजबूत वापसी का प्रमाण पेश किया है। कंपनी की हालिया बिक्री आंकड़ों के अनुसार, अब उसकी कुल कार बिक्री में आधी से अधिक हिस्सेदारी डीजल वेरिएंट्स की है। यह ट्रेंड SUV सेगमेंट में और स्पष्ट है, जहां डीजल की हिस्सेदारी 50% से ऊपर पहुंच गई है। M&M के पैसेंजर व्हीकल्स हेड विजय नाकरा ने कहा, ग्राहकों की पसंद डीजल की ओर झुक रही है, क्योंकि लंबी दूरी और बेहतर माइलेज के लिए यह पेट्रोल और इलेक्ट्रिक से आगे है। कंपनी की लोकप्रिय मॉडल्स जैसे थार, स्कॉर्पियो-N, XUV700 और बोलेरो में डीजल वेरिएंट्स की मांग 60-70% तक है। नवंबर 2025 में M&M ने 80,000 से अधिक यूनिट्स बेचीं, जिसमें डीजल का योगदान प्रमुख रहा।

यह बदलाव ऐसे समय आया है जब कई कंपनियां इलेक्ट्रिक और पेट्रोल पर फोकस कर रही हैं। लेकिन ग्रामीण और हाईवे उपयोगकर्ता डीजल को प्राथमिकता दे रहे हैं। BS6 नॉर्म्स के बाद डीजल इंजनों की दक्षता बढ़ी है, और कीमत अंतर (पेट्रोल से 1-2 लाख कम) ने इसे आकर्षक बनाया है। M&M ने डीजल में mHawk और mStallion इंजनों को अपग्रेड किया है, जो कम उत्सर्जन और अधिक पावर देते हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि डीजल की यह वापसी FY26 में भी जारी रहेगी, हालांकि EV सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रा से चुनौती मिलेगी। M&M का लक्ष्य 2030 तक 30% EV बिक्री है, लेकिन फिलहाल डीजल उसका मजबूत स्तंभ है। शेयर बाजार में कंपनी के शेयर 1.5% चढ़े। यह ट्रेंड भारतीय ऑटो बाजार की विविधता को दर्शाता है।

Vedanta's Bold Demerger and Aluminium Expansion: Unlocking Value in Metals Race

Six-Way Split to Sharpen Focus on Zinc, Oil, Aluminium; Odisha Refinery Hits 5 MTPA Milestone with Rs 3,000 Cr Investment

Mumbai: Vedanta Ltd is accelerating its transformation through a landmark six-way demerger while simultaneously scaling up its aluminium operations, positioning the group to compete more aggressively in global commodities.

The demerger, approved by the board, will carve out independent listed entities for aluminium, oil & gas, power, base metals (zinc-lead-silver), iron ore & steel, and ferrous materials, leaving Vedanta as a pure-play holding company. "This unlocks significant value by allowing each business to pursue tailored strategies, attract specialised investors, and optimise capital allocation, said Chairman Anil Agarwal. The restructuring, pending NCLT and shareholder approvals, aims for completion by FY27, potentially valuing the sum-of-parts at a 30-40% premium to the current market cap.

Concurrently, Vedanta Aluminium has ramped up its Lanjigarh refinery in Odisha to 5 million tonnes per annum (MTPA), up from 3.5 MTPA, with a Rs 3,000 crore investment. The expansion, commissioned ahead of schedule, boosts alumina production to feed downstream smelters, reducing import dependence and supporting India's aluminium demand growth of 10% annually. Lanjigarh's scale-up enhances cost competitiveness and sustainability, with 100% fly ash utilisation and renewable power integration," a company spokesperson noted.

The dual moves underscore Vedanta's pivot toward vertical integration and ESG compliance amid volatile metals prices. Analysts estimate the demerger could release Rs 50,000 crore in trapped value, while the refinery upgrade adds Rs 5,000 crore to annual EBITDA. Shares rose 3.2% to Rs 516, reflecting optimism. As India targets self-reliance in critical minerals, Vedanta's strategy signals a sharper, more agile conglomerate ready to race ahead in the global metals arena.

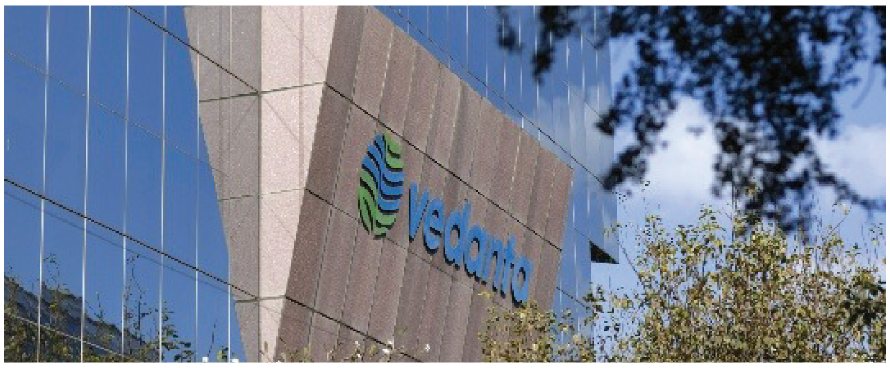

Ola Electric Founder Bhavish Aggarwal to Clear Rs 260 Cr Promoter Pledges, Eyes Debt-Free Status

Limited Stake Sale to Fund Unpledging; Move Signals Confidence Amid EV Market Challenges and Upcoming Launches

Mumbai: Ola Electric founder and CEO Bhavish Aggarwal has announced plans to fully release Rs 260 crore worth of promoter pledges by monetizing a limited portion of his stake, paving the way for a debt-free personal balance sheet. The decision, disclosed during the company's Q2 earnings call, aims to eliminate all encumbrances on shares pledged against loans, boosting investor confidence in the EV pioneer's long-term vision.
Aggarwal, who holds a significant stake in Ola Electric Mobility Ltd, clarified that the stake sale would be minimal and executed through secondary market transactions or block deals, without diluting the company's equity base. This is a personal financial restructuring to achieve zero debt while retaining substantial skin in the game, he stated. The proceeds will retire loans taken for personal investments, including in group entities like Ola Cabs and Krutrim AI.
The un-pledging comes amid Ola Electric's aggressive expansion, with new models like the Roadster motorcycle series and Gen 3 platform slated for 2026 launches. Despite reporting a widened Q2 loss of Rs 564 crore on revenue of Rs 1,240 crore, Aggarwal reiterated profitability targets by FY27, backed by cost optimisation and scale.

Analysts view the move positively, noting it removes overhang from pledged shares (previously 10-15% of promoter holding) and aligns with governance best practices. Ola Electric's market cap stands at Rs 35,000 crore, with shares trading at Rs 79 down 40% from its peak but up 5% post-announcement.
As India's EV penetration targets 30% by 2030, Aggarwal's debt-free stance signals commitment amid competition from Tata Motors and Bajaj Auto. The strategy underscores disciplined capital management in a capital-intensive sector.

Kotak Mahindra Bank Overhauls Microfinance Strategy: Slashes JLG Exposure Amid Sector Stress

Private Lender Shifts to Individual Lending and Digital Models; Targets Sustainable Growth as MFI NPAs Rise 2-3%

Mumbai: Kotak Mahindra Bank is revamping its microfinance portfolio by significantly reducing exposure to Joint Liability Group (JLG) loans, a traditional group-based lending model, in response to cyclical stress in the sector. The move, confirmed by bank executives during the Q2 earnings call, aims to mitigate risks from over-indebtedness and regional repayment challenges that have pushed industry NPAs up 2-3% in recent quarters.
Kotak, which had built a Rs 8,000 crore microfinance book primarily through JLG partnerships with MFIs, is now pivoting toward individual lending, salaried micro-loans, and digital-first products. We are consciously de-risking the JLG segment and focusing on granular, tech-enabled individual loans with better underwriting, said a senior official. The bank plans to cap JLG exposure at 20-25% of its microfinance portfolio by FY27, down from over 60% currently.

This strategic shift comes amid broader industry headwinds, including high borrower leverage in states like Tamil Nadu and Karnataka, and delayed monsoons impacting rural cash flows. RBI's recent warnings on unsecured lending have prompted several banks, including Kotak, to tighten norms. Kotak's microfinance disbursals dropped 15% YoY in H1 FY26, but asset quality remained stable with GNPA below 1.5%.
The bank is leveraging its digital platform for faster KYC, AI-driven credit scoring, and tie-ups with fintechs to expand reach among underserved women and semi-urban borrowers. Analysts view the overhaul positively, forecasting 12-15% CAGR in microfinance AUM over three years with lower delinquency.
Kotak's shares rose 1.8% to Rs 1,920 on BSE, reflecting investor confidence in the prudent recalibration. As India's microfinance sector eyes Rs 5 lakh crore by 2030, Kotak's pivot underscores the need for resilient, tech-backed models to navigate cyclical risks.

Novartis Doubles Down on India: Hyderabad to Host Largest Global R&D Hub Outside Switzerland

$1 Bn Investment Over Five Years; 5,000-Strong Team to Drive Oncology, Gene Therapy, and AI Innovations for Emerging Markets

Mumbai: Swiss pharmaceutical giant Novartis has announced plans to establish its largest global research and development (R&D) hub outside Switzerland in Hyderabad, India, with a staggering $1 billion investment over the next five years. The facility, set to be fully operational by 2028, will employ over 5,000 scientists and researchers, focusing on cutting-edge areas like oncology, gene therapy, neuroscience, and AI-driven drug discovery.

This strategic move underscores India's growing stature as a global innovation powerhouse, leveraging its vast talent pool of skilled professionals and cost-effective ecosystem. "India is pivotal to our global strategy. Hyderabad's new hub will accelerate breakthrough therapies tailored for emerging markets, including affordable solutions for diseases prevalent in low- and middle-income countries," said Vas Narasimhan, CEO of Novartis.The hub will integrate advanced technologies such as machine learning for clinical trials and precision medicine, complementing Novartis's existing centres in Basel and Cambridge. It builds on the company's 20-year presence in India, where it already operates a 1,000-strong R&D team. The investment aligns with India's 'Make in India' initiative and PLI scheme for pharmaceuticals, aiming to boost local manufacturing and exports.

Novartis's bet comes amid a surge in global pharma R&D shifting to India, with peers like Pfizer and Sanofi expanding footprints. The hub is expected to create thousands of high-skill jobs and foster collaborations with Indian academia and startups.

As India's pharma sector eyes $130 billion by 2030, Novartis's Hyderabad hub signals confidence in the country's potential to lead in life sciences innovation, delivering affordable, life-saving drugs worldwide.

Tatas Double Down on iPhone: Rs 1,500 Cr Fresh Infusion into Electronics Arm

Tata Electronics Boosts Capacity for Apple Assembly; Eyes 50% Share in India's Premium Smartphone Production by 2028

Mumbai: The Tata Group has deepened its electronics ambitions with an additional Rs 1,500 crore investment in Tata Electronics Pvt Ltd (TEPL), raising its total commitment to over Rs 20,000 crore. The fresh capital, approved by the board on Tuesday, will fuel expansion of iPhone assembly operations and component manufacturing, positioning the conglomerate as a cornerstone of India's 'Make in India' push in premium smartphones.

TEPL, which already operates Apple's iPhone assembly facilities in Hosur (Tamil Nadu) and Narasapura (Karnataka) through joint ventures with Pegatron and Wistron, plans to scale production to meet surging domestic and export demand. The investment will enhance backward integration, including display modules, camera components, and battery packs, reducing reliance on Chinese suppliers. "This infusion accelerates our vision of building a world-class electronics ecosystem, creating thousands of jobs and fostering innovation," a Tata spokesperson stated.

The move aligns with Apple's diversification from China, with Tata aiming for 50% of India's iPhone production by 2028 up from the current 15-20%. The group has already trained over 50,000 workers, mostly women, and partnered with global giants for technology transfer.

Analysts estimate the expanded capacity could generate Rs 50,000 crore in annual revenue by FY28, bolstering India's $50 billion electronics exports goal. Shares of Tata group firms, including Tata Technologies, rose 2-3% on BSE, reflecting optimism. As India targets $300 billion in electronics manufacturing by 2030, the Tatas' bet underscores private sector leadership in high-value tech, blending scale with sustainability.

SBI होम लोन पर बड़ी राहत: रेपो रेट कट के बाद ब्याज दर 0.25% घटी, अब 7.25% से शुरू

20 लाख के 20 साल लोन पर EMI में 600-800 रुपये मासिक बचत, कुल 74 हजार तक फायदा; अन्य बैंक भी जल्द दरें घटाएंगे

भोपाल: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने RBI के रेपो रेट में 0.25% कटौती के बाद होम लोन की ब्याज दरों में तुरंत कमी की घोषणा की है। अब SBI का होम लोन 7.25% से शुरू होगा, जो पहले 7.50% था। यह राहत नए और मौजूदा दोनों ग्राहकों को मिलेगी, जिससे EMI में उल्लेखनीय बचत होगी। SBI के चेयरमैन सीएस सेट्टी ने कहा, "हम ग्राहकों को तुरंत फायदा पहुंचा रहे हैं। क्रेडिट स्कोर के आधार पर दरें और कम हो सकती हैं।"

EMI में कितनी बचत होगी? उदाहरण के लिए, 20 लाख रुपये के 20 साल के होम लोन पर:

- पुरानी दर 7.50% पर EMI: लगभग ₹16,100
- नई दर 7.25% पर EMI: लगभग ₹15,500 मासिक बचत: 600-800 रुपये कुल ब्याज बचत: करीब 74,000 रुपये

30 लाख लोन पर बचत इससे दोगुनी हो सकती है। मौजूदा ग्राहक बैंक की वेबसाइट या ब्रांच से रीसेट करवा सकते हैं। SBI ने MCLR को भी 0.25% घटाकर 8.20% किया।

यह कटौती RBI के 5 दिसंबर के फैसले के बाद आई है, जहां रेपो रेट 5.25% हो गया। अन्य बैंक जैसे HDFC, PNB और BoB भी जल्द दरें घटाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि यह आवास बाजार को गति देगा, जहां FY26 में 1.5 लाख करोड़ के होम लोन वितरित होने का अनुमान है। ग्रामीण और मध्यम वर्ग के लिए यह बड़ा तोहफा है। हालांकि, क्रेडिट स्कोर 750 से ऊपर होने पर सबसे कम दर मिलेगी। SBI के शेयर 1.8% चढ़े। यह राहत त्योहारी सीजन के बाद घर खरीदने वालों को प्रोत्साहित करेगी।

कोटक म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF: NFO अलर्ट

19 दिसंबर से 2 जनवरी तक NFO ओपन, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा; लो-कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टमेंट का अवसर

जयपुर: कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF का लॉन्च करने की घोषणा की है। यह नया फंड ऑफर (NFO) 19 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन रहेगा। यह ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स को ट्रैक करेगा, जिसमें निफ्टी 50 के बाद की 50 सबसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं।

कोटक म्यूचुअल फंड के अनुसार, यह ETF निवेशकों को भारत की उभरती ब्लूचिप कंपनियों में लो-कॉस्ट पैसिव इन्वेस्टमेंट का अवसर देगा। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में फाइनेंशियल, कंज्यूमर गुड्स, आईटी और इंडस्ट्रियल सेक्टर की प्रमुख कंपनियां हैं, जो लंबी अवधि में उच्च ग्रोथ पोटेंशियल रखती हैं।

पिछले 10 वर्षों में इस इंडेक्स ने निफ्टी 50 से बेहतर रिटर्न दिया है। NFO में यूनिट्स का फेस वैल्यू ₹10 होगा। मिनिमम इन्वेस्टमेंट ₹100 और उसके मल्टीपल में होगा। ETF NSE और BSE पर लिस्ट होगा, जिससे लिक्विडिटी सुनिश्चित होगी। फंड का एक्सपेंस रेशियो इंडेक्स फंड्स की तुलना में कम रखा जाएगा। कोटक AMC के सीईओ नीलेश शाह ने कहा, "यह ETF मिड-कैप और लार्ज-कैप के बीच का ब्रिज है, जो डायवर्सिफिकेशन और ग्रोथ का संतुलन देगा।" विशेषज्ञों का मानना है कि पैसिव फंड्स में इनफ्लो बढ़ रहा है, और यह ETF रिटेल निवेशकों को आकर्षित करेगा। FY26 में पैसिव AUM 20% बढ़ने का अनुमान है। यह लॉन्च कोटक के पैसिव प्रोडक्ट्स पोर्टफोलियो को मजबूत करेगा। निवेशक डीमैट अकाउंट से सब्सक्राइब कर सकते हैं।

kotak
Mutual Fund

MPBIL/2013/49052
INVESTMENT AVENUES®
(इन्वेस्टमेंट ऐवेन्युस)
(A Publication of Vision Invest Tech Pvt. Ltd.)

INVESTMENT AVENUES
CALL FOR ARTICLES
Share Your Knowledge with
INVESTMENT AVENUES
We invite individual, professionals, and entrepreneurs to contribute their expertise and experiences.

- STOCK MARKET
- MUTUAL FUNDS
- REAL ESTATE
- STARTUPS & ENTREPRENEURSHIP

Guidelines:
1. Article must be original
2. Submit in MS Word format
3. Length should not exceed 500 words

editor@investmentavenues.in
write with us, inspire others, and make your voice heard in the world of investments!

INVESTMENT AVENUES®
Looking To Invest In Real Properties & Valued Businesses In BhopaL
Discover genuine real estate and well-assessed business opportunities — safe-to-invest and growth-oriented.
Secure Deals. Smart Investments.

EMAIL: INVESTMENTAVENUES90@GMAIL.COM
CONTACT: +91 73899 26586

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

• As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
• If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
• If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
• Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
• If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
• If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	losing Rat	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	25966	26420	26233	26100	25913	25780	25593	25460
BANK NIFTY	59069	60315	59924	59496	59105	58677	58286	57858
SENSEX	84929	86428	85853	85391	84816	84354	83779	83317
FINNIFTY	27378	28128	27888	27633	27393	27138	26898	26643
MIDCAP	13862	14279	14081	13971	13773	13663	13465	13355
ACC	1754	1822	1805	1780	1763	1738	1721	1696
AXISBANK	1231	1346	1318	1274	1246	1202	1174	1130
ABCAPITAL	349	380	372	360	352	340	332	320
BHARTIARTL	2091	2186	2156	2123	2093	2060	2030	1997
BHEL	275	297	292	283	278	269	264	255
BIOCON	398	422	411	405	394	388	377	371
CDSL	1497	1575	1549	1523	1497	1471	1445	1419
DATAPATTERN	2550	2810	2714	2632	2536	2454	2358	2276
ESCORTS	3614	3883	3817	3715	3649	3547	3481	3379
EICHERMOTOR	7227	7529	7384	7305	7160	7081	6936	6857
FEDERAL BANK	268	277	273	270	266	263	259	256
GRINFRAPOJECT	1013	1075	1060	1036	1021	997	982	958
HDFCBANK	985	1029	1016	1000	987	971	958	942
HCLTECH	1641	1730	1708	1675	1653	1620	1598	1565
HINDUNILVR	2281	2355	2328	2305	2278	2255	2228	2205
HAL	4303	4513	4428	4365	4280	4217	4132	4069
HYUNDAI	2310	2406	2365	2337	2296	2268	2227	2199
IOC	163	179	174	169	164	159	154	149
ICICIBANK	1354	1395	1383	1368	1356	1341	1329	1314
INFY	1636	1732	1693	1664	1625	1596	1557	1528
ITC	401	412	409	405	402	398	395	391
KOTAKBNK	2160	2222	2208	2184	2170	2146	2132	2108
LICHOUSING	532	552	543	538	529	524	515	510
LT	4075	4183	4141	4108	4066	4033	3991	3958
LUPIN	2124	2224	2185	2155	2116	2086	2047	2017
MARUTI	16405	16805	16652	16529	16376	16253	16100	15977
M&M	3602	3785	3723	3663	3601	3541	3479	3419
MGL	1150	1222	1190	1170	1138	1118	1086	1066
MAZGAONDOC	2407	2611	2538	2472	2399	2333	2260	2194
PFC	339	359	352	345	338	331	324	317
RECLTD	339	356	350	344	338	332	326	320
RELIANCE	1565	1620	1597	1581	1558	1542	1519	1503
SBIN	980	1014	998	989	973	964	948	939
SUNPHARMA	1746	1849	1825	1785	1761	1721	1697	1657
SHRIRAMFINANCE	905	1001	958	931	888	861	818	791
TITAN	3934	4122	4042	3988	3908	3854	3774	3720
TCS	3286	3466	3392	3339	3265	3212	3138	3085
TATAMOTORS	354	377	366	360	349	343	332	326
UPL	751	801	786	768	753	735	720	702
VALIENT	265	294	285	275	266	256	247	237
WIPRO	264	276	271	268	263	260	255	252

राजमार्ग निर्माण की रफ्तार 60 किमी/दिन तक बढ़ाने का लक्ष्य: नितिन गडकरी

2025-26 में 15,000 किमी हाईवे बनाने की योजना, 50 लाख करोड़ का निवेश; PPP मॉडल और BOT से तेजी

नई दिल्ली: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सरकार राजमार्ग निर्माण की गति को बढ़ाकर 60 किलोमीटर प्रतिदिन करने का लक्ष्य रख रही है। वर्तमान में यह गति 35-40 किमी/दिन है। गडकरी ने एक कार्यक्रम में कहा, हम 2025-26 में 15,000 किलोमीटर हाईवे बनाने जा रहे हैं। अगले पांच वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा, जो रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देगा।"

गडकरी ने बताया कि पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल और बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (HAM) से जोखिम कम हुआ है, जिससे निजी निवेश बढ़ा है। सरकार ने EPC मॉडल में भी सुधार किए हैं। मंत्री ने कहा, हमारी दृष्टि है कि भारत विश्व स्तरीय सड़क नेटवर्क वाला देश बने। इससे लॉजिस्टिक्स लागत 13% से घटकर 9% हो जाएगी।

2024-25 में 12,000 किमी हाईवे बने, जो रिकॉर्ड है। गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स का उदाहरण दिया, जो समय से पहले पूरे हो रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित राजमार्ग नीति लागू की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य विकसित भारत 2047 को मजबूत करेगा। इससे 1 करोड़ नौकरियां सृजित होंगी। गडकरी ने राज्यों से सहयोग की अपील की। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था और व्यापार को बढ़ावा देगी।

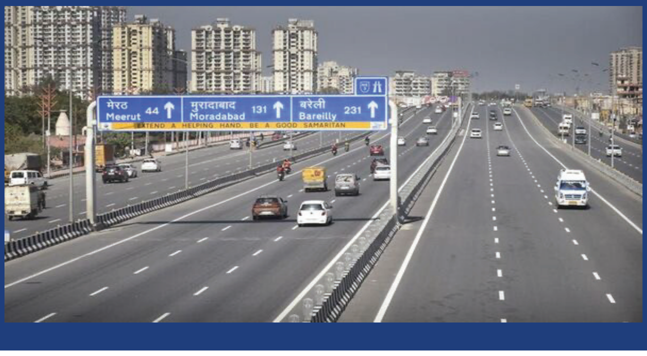

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in